

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
|------------|--|---|
| 26.11.2024 | <p>न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 20.11.2024 के क्रम में पत्रावली पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।</p> <p>अधिवक्ता अपीलान्ट ने निवेदन किया कि पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल अजमेर से दोनों पक्षों को सुनकर निर्णय करने हेतु सहायक कलक्टर भीम को रिमाण्ड की गयी थी, किन्तु राजस्व कर्मचारियों की गलती से पत्रावली फैसल शुदा समझकर राजस्व रेकार्ड में डाल दी गयी तथा लम्बे समय तक अपीलान्ट को कोई सूचना नहीं दी गयी। बाद में अपीलान्ट अपने जानकार के साथ सहायक कलक्टर देवगढ़ में जाकर फाईल ढुढवाई तो उक्त पत्रावली रेकार्ड रूम में अस्त-व्यस्त कागजों में पड़ी हुई मिली, जिस पर पत्रावली सहायक कलक्टर देवगढ़ द्वारा दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये, किन्तु पक्षकारों के नहीं आने से कार्यवाही ड्रॉप करने का आदेश देकर पत्रावली फैसल शुमार कर दी, जबकि आदेश 9 नियम 3 में दोनों पक्षकारों के अनुपस्थिति रहने से वाद को निरस्त किया जाता है, न कि ड्रॉप किया जाता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 67/2011 में पारित निर्णय दिनांक 16.02.2011 निरस्त किया जाकर प्रकरण में विधिवत सुनवाई कर निर्णय पारित किये जाने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जावे।</p> <p>उक्त बहस का खण्डन करते हुए रेस्पोंडेन्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को विधि सम्मत बताते हुए अपील खारिज करने का निवेदन किया।</p> <p>हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय आदेश दिनांक 16.02.2011 अनुसार प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर से रिमाण्ड होने पर दोनों पक्षों की अनुपस्थिति के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कार्यवाही ड्रॉप करते हुए अपील फैसल शुमार कर दी, जो विधि सम्मत नहीं है, क्योंकि आदेश 9 नियम 3 सी.पी.सी. अनुसार जहां दोनों पक्षकार अनुपस्थिति हो वहां वाद खारिज किया जाता है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने वाद में ड्रॉप का आदेश दिया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।</p> <p>अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 67/2010 आदेश दिनांक 16.02.2011</p> | |



अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश की पालना में पक्षकारान को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर विधिक प्रक्रिया के तहत प्रकरण का निस्तारण करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 20.01.2025 को उपस्थित रहे। निर्णय आज दिनांक 26.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कीर्ति राठौड़)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर